

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1774/2024

राजेश जैन

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति.मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता सह अति.शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 24.05.2024

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थागण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में निलम्बन आदेश दिनांक 09.02.2024 (अनुलग्नक-1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध नियम-16 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन होना मानते हुए निलम्बित किया गया था। अपीलार्थी का यह कथन है कि निलम्बन आदेश दिनांक 09.02.2024 पारित होने के बाद तीन माह तक कोई आरोप पत्र अपीलार्थी को नहीं किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान में अपीलार्थी को दिनांक 22.05.2024 को आरोप पत्र दिया गया है, जो आरोप पत्र सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के द्वारा अपना कार्यालय शिफ्ट करने बाबत अधीक्षक अभियंता, अलवर को निवेदन किये जाने के आधार पर दिया गया है। आरोप पत्र में यह माना गया है कि उक्त अधिकारी अपीलार्थी का नियंत्रक अधिकारी नहीं है एवं इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। आरोप पत्र

में यह भी वर्णित है कि लगभग उसी समय प्राईवेट व्यक्ति द्वारा बाउन्ड्रीवाल मय गेट का निर्माण कर डाक बंगला की रिक्त भूमि पर कब्जा किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि सीसीए नियम 17 के तहत केवल लघुशास्ति ही दी जा सकती है। ऐसे में अपीलार्थी को निलम्बित किया जाना उचित नहीं है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है, जिससे कि जांच प्रभावित नहीं हो। निलम्बन आदेश की पुष्टि कार्मिक विभाग द्वारा की गयी है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं का खण्ड कार्यालय शिफिटिंग करने हेतु रिकॉर्ड के अनुसार अपने स्वयं के प्रशासनिक नियन्त्रण अधिकारी को ना लिखा जाकर, अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. सिविल वृत्त अलवर को लिखा गया। विद्युत खण्ड कार्यालय के पास स्थित भूमि पर निजी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर कब्जा कर लिया गया। अपीलार्थी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता के पत्रांक अलवर 132/अनुभाग 08/डी-77 दिनांक 08.04.2024 के द्वारा प्रशासनिक विभाग को प्रेषित किये गये हैं।
3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. अपीलार्थी को जिस समय निलम्बित किया गया था, उस समय अपीलार्थी के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु वर्तमान में यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही नहीं की जा रही है। अपीलार्थी के विरुद्ध सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही किये जाने का आरोप पत्र एवं ज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जिस सीसीए नियम 16 की कार्यवाही किये जाने का आधार मानते हुए अपीलार्थी को निलम्बित किया गया था, वह आधार अब समाप्त हो चुका है।
5. माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम अशोक कुमार अग्रवाल (2013)16एससीसी 147 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:—

"23. The scope of interference by the Court with the order of suspension has been examined by the Court in a large number of cases, particularly in [State of M.P. v. Sardul Singh](#), (1970) 1 SCC 108; [P.V. Srinivasa Sastry v. Comptroller & Auditor General of India](#), (1993) 1 SCC 419; [Director General, ESI &](#)

Anr. v. T. Abdul Razak, AIR 1996 SC 2292; Kusheshwar Dubey v. M/s Bharat Cooking Coal Ltd. & Ors., AIR 1988 SC 2118; Delhi Cloth General Mills vs. Kushan Bhan, AIR 1960 SC 806; U.P. Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad & Ors. v. Sanjeev Rajan, (1993) Supp. (3) SCC 483; State of Rajasthan v. B.K. Meena & Ors., (1996) 6 SCC 417; Secretary to Govt., Prohibition and Excise Department v. L. Srinivasan, (1996) 3 SCC 157; and Allahabad Bank & Anr. v. Deepak Kumar Bhola, (1997) 4 SCC 1, wherein it has been observed that even if a criminal trial or enquiry takes a long time, it is ordinarily not open to the court to interfere in case of suspension as it is in the exclusive domain of the competent authority who can always review its order of suspension being an inherent power conferred upon them by the provisions of Article 21 of the General Clauses Act, 1897 and while exercising such a power, the authority can consider the case of an employee for revoking the suspension order, if satisfied that the criminal case pending would be concluded after an unusual delay for no fault of the employee concerned. Where the charges are baseless, mala fide or vindictive and are framed only to keep the delinquent employee out of job, a case for judicial review is made out. But in a case where no conclusion can be arrived at without examining the entire record in question and in order that the disciplinary proceedings may continue unhindered the court may not interfere. In case the court comes to the conclusion that the authority is not proceeding expeditiously as it ought to have been and it results in prolongation of sufferings for the delinquent employee, the court may issue directions. The court may, in case the authority fails to furnish proper explanation for delay in conclusion of the enquiry, direct to complete the enquiry within a stipulated period. However, mere delay in conclusion of enquiry or trial can not be a ground for quashing the suspension order, if the charges are grave in nature. But, whether the employee should or should not continue in his office during the period of enquiry is a matter to be assessed by the disciplinary authority concerned and ordinarily the court should not interfere with the orders of suspension unless they are passed in mala fide and without there being even a prima facie evidence on record connecting the employee with the misconduct in question.

24. Suspension is a device to keep the delinquent out of the mischief range. The purpose is to complete the

proceedings unhindered. Suspension is an interim measure in aid of disciplinary proceedings so that the delinquent may not gain custody or control of papers or take any advantage of his position. More so, at this stage, it is not desirable that the court may find out as which version is true when there are claims and counter claims on factual issues. The court cannot act as if it an appellate forum de hors the powers of judicial review."

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा किशनाराम विश्नोइ के मामले में निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया है :-

"Having considered this factual position and especially looking to the fact that the petitioner is subjected to disciplinary proceedings only under Rule 17 of the Rules of 1958, prima facie I am of the view that in such matters, suspension is not warranted.

Be that as it may, no effect has been given to the order of suspension in view of the interim order passed by this court on 26.08.2011. The reasons and the administrative exigency, if any, existing while placing the petitioner under suspension must not be existing now, specially looking to the fact that no effect is given to the suspension so far. As such, I don't find any just reason to continue the order of suspension. Accordingly, this petition for writ is allowed. The order dated 28.07.2011 passed by the District Education Officer (Secondary), Jalore is quashed. Expeditious disposal of the enquiry pending against the petitioner under Rule 17 of the Rules of 1958 is desirable."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा गुलाम हुसैन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निम्नलिखित कथन किया गया है :-

"Rajasthan Civil Service (Classification, Control & Appeal) Rules, 1958, Rr. 13, 14, 16, 17 Scope -

Petitioner proceeded against under Rule 17 instead of under Rule 16 Misconduct alleged against Petitioner not so grave, as to attract major penalty covered by Rule 14 - Suspension of Petitioner brought about in abuse of powers under Rule 13 and contrary to instructions contained in various circulars - Suspension of Petitioner mala-fide and not equally justified Order of Petitioner's suspension quashed."

इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णयों में 17 सीसीए नियम के अंतर्गत कार्मिक को निलंबन किया जाना उचित नहीं माना है। 17 सीसीए नियम के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही में लघु दण्ड का प्रावधान है।

7. हम यह पाते हैं कि जो चार्जशीट अपीलार्थी को दी गयी है, उसमें ऐसा कोई मामला अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं है, जिसके आधार पर अपीलार्थी को निलम्बित किया जाना उचित प्रकट होता हो। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी को पूर्व में निलम्बन सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित होना मानते हुए किया गया था, परन्तु अब अपीलार्थी के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसे में निलम्बन आदेश पारित करते समय जो आधार रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम निलम्बन आदेश को उचित होना नहीं पाते हैं।
8. परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के विरुद्ध पारित किया गया निलम्बन आदेश दिनांक 09.02.2024 अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को पुनः सेवा में बहाल किया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध लम्बित सीसीए नियम 17 की कार्यवाही पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)